प्रिंटिंग प्रेसों पर बिक्री कर

***1112. श्री राम चरण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उन प्रिंटिंग प्रेसों से बिक्री कर लिया जाता है जो एक वर्ष में स्कूलों और कालिजों के 12,000 रुपये से अधिक के परीक्षा पत्र छापते हैं जबकि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में परीक्षा पत्र छापने पर बिक्री कर लिये जाने के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषमता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में 12,000 रुपये की सीमा को समाप्त कर परीक्षा पत्र छापने वाले सभी प्रिंटिंग प्रेसों से समान दर पर बिक्री कर लेने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) छापेखानों द्वारा किये गये छपाई के काम पर, चाहे वह परीक्षा पत्रों का हो अथवा अन्य किसी प्रकार का, उत्तर प्रदेश अथवा दिल्ली में बिक्री कर नहीं लगता है। लेकिन, छपाई के काम के अलावा अगर छापे खाने माल भी बेचते हैं तो उस माल की बिक्री पर उन छापे खानों को उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह बिक्री कर देना पड़ता है, बशर्ते कि उनके द्वारा किया गया वह वार्षिक व्यवसाय क्रमशः, 12,000 रुपये और 10,000 रुपये से अधिक का हो।

(ख) और (ग). चूंकि उत्तर प्रदेश में किये गये वार्षिक व्यवसाय विषेयक 12,000 रुपये वाली सीमा राज्य के सभी व्यापारियों को लागू होती है, इसलिये छापेखाने के मामले में इस बारे में किसी प्रकार का अपवाद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का दिया जाना

***1114. श्री मधु लिमये :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं ;

(ख) उन पर कुल कितनी राशि खर्च की जा रही है ;

(ग) क्या इस राशि को बढ़ाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विकलांग विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिये राज्य सरकारों और कम से कम विश्वविद्यालयों के परामर्श से कोई व्यवस्था करने का है ?

समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती फूल रेनु गुहा) : (क) विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–818/38]

(ख) 1967–68. . . 4.92 लाख रुपये

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students

*1115. SHRI MARANDI: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering a proposal to enhance the income limit for the grant of scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students keeping in view the increase in prices;

(b) whether it is also a act that the income basis is being withdrawn for the grant of such scholarships; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Indian Oil Corporation

*1117. SHRI ABDUL GHANI DAR: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the assets of an Officer of the Head Office of the Indian Oil Corporation, Bombay were investigated by the C.B.I. and they found Rs. 2½ lakhs in cash and Rs. 15 lakhs in foreign banks;

(b) whether it is also a fact that the same officer has been promoted; and

(c) if so, on what basis promotion has been given to him?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH): (a) No, Sir. But the Central Bureau of Investigation are investigating a case against an Engineering Manager of the Indian Oil Corporation (Marketing Division), Bombay, and the Bureau has found assets to the tune of Rs. 1,41,405 in the possession of that officer, either in his own name or in the name of his dependents.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Levy on Agricultural Income-tax

*1118. SHRI RAMACHANDRA ULAKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 344 on the 14th February, 1968 and state:

(a) whether the suggestion of the Planning Commission to levy agricultural Income-tax and also to have uniform tax on Agricultural Income, have since been considered; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): (a) As stated earlier on the Floor of this House, the matter was discussed at the last meeting of the National Development Council held on 1-2 December 1967 and referred to State Governments for consideration. The matter is still under consideration by State Governments.

(b) Does not arise.

Controller of Defence Accounts for Southern Command

*1119. SHRI ANBUCHEZHIAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are large military establishments in the South whose Finance Office is situated in Poona; and

(b) if so, whether there is any proposal for setting up a separate office of the Controller of Defence Accounts with Headquarters at Madras or Bangalore for Southern Command?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): (a) Yes, Sir. The Headquarters office of the Controller of Defence Accounts, Southern Command is situated in Poona.

(b) No, Sir.

बैंकों द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेश

*1120. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अधीन विभिन्न बैंकों, समवायों और निगमों द्वारा 15 जनवरी,